[شری محمد خلیل الرحمان]

بصورت دیگر ان مقدس مقامات کے تمام میں رہائش کی سہولت نہ دی جائے تو حیدرآبادی حجاج کے ساتھ سراسر نا انصافی تصور کیا جائیگا - اسکے علاوہ ہندوستان کے مختلف ریاستوں نے رباطیں بنوائی ہوئی رباط - لکھنؤ رباط موجود ہے - ان علاقوں کے عازمین حج کو بھی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں مفت سہولت حاصل ہے - اسمیں بھی رہائش کی بابت رقم کی ادائیگی سے مستثنیٰ قرار دیں - حیدرآبادی حجاج کو رہائش کے بابت پیشگی ایک ہزار روپئے کے بدلے ترافت کے لزوم کو برخواست کیا جائے - میں وزارت خارجہ حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں حیدرآباد حج کمیٹی بمبئی کو خصوصی ہدایات دے -

Allocation of more funds for expeditioos completion of Indira Gandhi Canal in Rajasthan

श्री भंवर लाल पंवार (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, इस विशेष उल्लेख के द्वारा आपके माध्यम से भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय एवं परियोजना मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। भारतवर्ष के पश्चिमी-भूभाग राजस्थान प्रदेश एवं विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के लिए भारतवर्ष के नव-निर्माणकर्ता स्वर्गीय प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल जी नेहरू ने पेय जल एवं सिंचाई की समस्या का निवारण करने के उद्देश्य से राजस्थान नहर परियोजना सन् 1958 में रुपये 66.46 करोड़ की लागत से सन् 1968-69 की अवधि में सम्पूर्ण करने की बनाई थी। इस परियोजना की लागत समय समय पर बढ़ती गई जो आज तक प्रारम्भ से 30 गुना अधिक होकर दो हजार करोड़ की हो गयी और फिर भी पूरी नहीं हो पायी है परियोजना के प्रारम्भ कि प्रथम दशक में केवल पांच करोड़ प्रतिवर्ष, द्वितीय दशक में केवल 15 करोड़ प्रतिवर्ष एवं तृतीय दशक में 30 करोड़ प्रतिवर्ष की लागत से इस परियोजना का कार्य बिल्कुल मंथर गति से कछुआ चाल से चल रहा है और यदि यही गति रही तो न जाने कब तक यह पूरी हो पायेगी। लगता है कि यह परियोजना द्रोपदी का चीर सी बन गयी है। केवल राजस्थान पर ही आर्थिक भार डाल उसके बलबूते से इस परियोजना को सम्पूर्ण होना बिल्कुल असंभव सा लग रहा है। और इसीलिए राजस्थान सरकार ने विश्व बैंक से आठ सौ करोड़ की राशि का ऋण दिलाने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक प्रोजेक्ट भेजा है वह भी अभी तक विचाराधीन है। इस परियोजना के पूर्ण करने में स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने काफी रुचि दिखाई और वर्तमान नौजवान प्रधान मंत्री माननीय श्री राजीव गांधी जी भी इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने के लिए निर्देश देते हुए अतिरिक्त धन राशि भी उपलब्ध करा रहे हैं। परन्तु इस परियोजना पर लगे प्रशासनिक अधिकारी गण एवं राज्य स्तर पर कार्यरत सम्बन्धित जन प्रतिनिधि गण का जिस समर्पण भावना से योगदान होना चाहिए था वह नहीं हो रहा है। इस परियोजना का नामकरण इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के पश्चात् कार्य में गति आयी है और प्रथम चरण पूरा हुआ है। द्वितीय चरण में सहायक नहरों एवं नालों का निर्माण होना बाकी है। इसके साथ ही नहरी भूमि की काश्त के लिए आवंटन भी नगण्य सा है। भारी तादाद में आवंटन के लिए आवेदन पत्र कालोनाइजेशन कमिश्नर के पास लम्बित हैं और भूमि का आवंटन नहीं होने के कारण परियोजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। इस परियोजना के लिए पूरा जल सुरक्षित करने के उद्देश्य से माननीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी ने पंजाब एकार्ड के द्वारा भी राजस्थान का सम्पूर्ण हित सुरक्षित रखा।

परन्तु सिंचाई के लिए जल का प्रयोग नहीं होने से राजस्थान-वासियों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है।

इस परियोजना के प्रथम चरण पूरे होने पर भी इस नहर की जल की बहाव क्षमता जो 18 हजार क्यूसिक फिट है वह भी पूरा पानी इस नहर में उपलब्ध नहीं हो रहा है क्योंकि आंधी और तूफान से इस मुख्य नहर का लगभग आधा भाग रेत से भर गया है और पानी के वर्तमान बहाव की क्षमता केवल 10 हजार क्यूसिक फिट ही रह गई है। रेत इतने लम्बे अरसे से भरी हुई है कि उस पर घास उग कर मवेशी का चरना प्रारम्भ हो गया है। मुख्य नहर की सफाई समय पर नहीं होने के कारण पानी का बहाव कम हो गया है। नहर की सफाई के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है जो राजस्थान सरकार के वश का रोग नहीं रहा है।

राजस्थान का पश्चिमी भाग पूरे भारतवर्ष में अकाल से सबसे अधिक पीड़ित होता रहा है। वहां पर पेय जल की भी समस्या इतनी गम्भीर है कि जनशक्ति एवं मवेशी का जिन्दा रहना दुश्वार हो गया है। मुख्य नहर से जोधपुर तक पेय जल व सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 200 किलोमीटर नहर का निर्माण होना है जिसके लिए राज्य सरकार ने सन् 1989-90 तक की अवधि निर्धारित की है। परन्तु कार्य की गति को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस अवधि में पेय जल भी जोधपुर सम्भाग को मिलना लगभग असम्भव सा दीख रहा है।

अतः आपके माध्यम से भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय एवं परियोजना मंत्रालय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस परियोजना को पूरी करने के लिए अतिरिक्त धन केन्द्र द्वारा आवंटित किया जाए कार्य को पूरा करने के लिए सिलट्रो का सहयोग प्राप्त किया जाए और इस विशाल परियोजना की लम्बी अवधि को देखते हुए पूर्व में राजस्थान सरकार का जो अनुरोध इस परियोजना को केन्द्रीय परियोजना घोषित करने का टर्न डाऊन कर दिया गया था उस पर पुनर्विचार का इस परियोजना को केन्द्रीय परियोजना घोषित कर अतिशीघ्र पूरी कराई जाए। अगले सत्र में इस परियोजना के संबंध में अल्पकालिक चर्चा कराई जाए। अन्त में मैं इस परियोजना का संक्षेप विवरण इस पद के माध्यम से कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं :-

नेहरू ने कहा था लहकेगी धरती भी राजस्थान की
जब बांह जुड़ेगी हिमगिरि से तपते हुए रेगिस्तान की।
जो प्यास बुझाती बंजर की जीवन में हरेरी हो जाती।
वो तीससाल से "इन्दिरा नहर" सूखी है कथा निर्माण की।।

मेरी इन भावनाओं को उपरोक्त पद में उल्लेखित करने में मेरे साथी सांसद श्री बेकल "उत्साही" के सहयोग के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे इस विषय पर विशेष उल्लेख देने का जो समय दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा० अबरार अहमद खान (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं भी इसका समर्थन करता हूं और अपने आपको इससे एसोसियेट करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : आप तो पहले यहां थे ही नहीं। आपको पहले यहां होना चाहिये था।

Lock-out in Titagarh Paper Mills

श्री मोहम्मद अमीन : (पश्चिमी बंगाल) : मैं आपके जरिये हुकूमते हिन्द की तवज्जोह टीटागढ़ पेपर मिल की तरफ दिलाना चाहता हूं।